Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 19-12-2006

Participants : Singh Dr. Raghuvansh Prasad

>

Title: The Minister of Rural Development made a statement regarding status of implementation of the components of Bharat Nirman relating to the Ministry of Rural Development .

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण के संघटकों के कार्यान्वयन की स्थिति से सम्बन्धित वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूँ :

भारत सरकार के अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम ' भारत निर्माण ' के छह घटकों में से तीन घटकों यथा ग्रामीण पथ, ग्रामीण आ वास एवं ग्रामीण पेयजल का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है । इन तीनों घटकों पर भारत निर्माण के लिए निर्धारित कुल बजट 1,74,000 करोड़ रुपए का लगभग आधा 85,000 करोड़ रुपए का उपयोग ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चार वर्षों में 2009 तक किया जाना है । मैं इन तीनों कार्यक्रमों की अद्यतन प्रगति के बारे में सदन को सूचित करना चाहता हूं ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शुरू से लेकर अब तक 1,94,740 कि.मी. लम्बाई की सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिनसे लगभग 60,000 बसावटों का सम्पर्क स्थापित होगा । इनकी लागत 36,994 करोड़ रुपए है ।

माह नवम्बर, 2006 तक कुल एक लाख कि.मी. लम्बाई की सड़कों का निमाण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिससे 30,000 बसावटों का सम्पर्क स्थापित हो गया है । योजना में अब तक 17056 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं । वर्ा 2000 से 2004 तक 2500 करोड़ सालाना खर्च हुआ जबकि वर्ा 2005-06 में 4200 करोड़ और इस वर्ा 9050 करोड़ खर्च कर, अगले दो वर्षों में 35,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है ।

वर्तमान सरकार ने इस कार्यक्रम को अत्यधिक गति प्रदान की है, जो इस तथ्य से विदित है कि पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा 81,120 कि.मी. लम्बाई की सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी लागत 20,332 करोड़ रुपए है ।

---

* Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 5755/06

सरकार ने भारत निर्माण के अंतर्गत यह लक्ष्य रखा है कि 1000 से अधिक की जनसंख्या वाले 40,436 गांवों (पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या वाले 26,366 गांवों), इस प्रकार सभी 66,802 गांवों को वर्ा 2009 तक अनिवार्य रूप से सर्वमौसमी पथों से जोड़ा जाएगा, जिसमें कुल 48,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे । 1,46,185 कि.मी. लम्बाई की नयी सड़कों और 1,94,130 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का उन्नयन होना है ।

सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने को सर्वोच्च महत्व दिया गया है । तदनुसार, त्रिस्तरीय गुणवत्ता निगरानी पद्धति विकसित की है । जन-साधारण की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कार्य स्थल पर नागरिक सूचना बोर्ड लगाने की व्यवस्था की गई है । साथ ही कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता हेतु ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी तथा लेखांकन प्र णाली (ओएमएमएएस) एवं तकनीकी अंकेक्षण की व्यवस्था विकसित की गयी है ।

भारत निर्माण के दूसरे घटक, ग्रामीण आवास में, 4 वर्ों में 60 लाख मकान बनाने का लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत प्रतिर्वा 15 लाख घरों का निर्माण कार्य इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत किया जा रहा है । इस वित्तीय वर्ा में इन्दिरा आवास योजना का बजटीय उपबंध 2920 करोड़ रुपए है, जिसके विरुद्ध 1455 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं और 4 लाख 90 हजार घरों का निर्माण कार्य कराया जा चुका है । इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में लाभान्वितों के चयन में पारदर्शिता बनाने के लिए वर्ा 2002 बी.पी.एल. सर्वे के आधार पर गरीबी के क्रम में " इन्दिरा आवास योजना स्थायी प्रतीक्षा सूची " बनाकर इस सूची को स्कूल अथवा पंचायत भवन की दी वार पर लिखवाया जाना , जिले की वेबसाइट पर डालना और पुस्तिका छपवाने की व्यवस्था लागू की गई है ।

कार्यक्रम के तीसरे घटक ग्रामीण पेयजल के अंतर्गत, भारत निर्माण में अब तक 1826 अनाच्छादित 14,666 आंशिक रूप से आच्छादित, 118535 स्लिपड बैक तथा 5151 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है । वर्ा 2009 तक 3052 अनाच्छादित, 38894 आंशिक रूप से आच्छादित, 252060 स्लिपड बैक तथा 147576 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा । पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्वजलधारा एवं नेशनल वाटर क्वालिटी मानिटरिंग एवं सर्विलेंस कार्यक्रम चालू किया गया है । सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पिछले दो वर्ों में अत्यधिक तीव्र गति से उपलब्धि सुनिश्चित की गई है । पिछले वर्ा 97 लाख ग्रामीण शौचालयों का निर्माण कराया गया है । देश के 569 जिलों को सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित किया जा चुका है । वर्ा 2001 तक देश के ग्रामीण इलाकों में 22 प्रतिशत घरों में शौचालयों की व्यवस्था भी उस को बढ़ाकर अब तक 40 प्रतिशत घरों में शौचालयों की व्यवस्था हो गयी है और वर्ा 2012 तक देश के सम्पूर्ण स्वच्छता आच्छादन का लक्ष्य रखा गया है । 31 मार्च, 2007 तक सभी विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय की अनिवार्य व्य वस्था करने का लक्ष्य रखा गया है ।

कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार का प्रावधान किया गया है । निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 में 40 पंचायतों को, वर्ा 2006 में 770 पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किया गया तथा वर्ा 2007 में 9703 ग्राम पंचायतों, 120 प्रखंडों तथा 2 जिला पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

इस प्रकार भारत निर्माण कार्यक्रम पूरी सफलता की ओर जा रहा है, जिसमें सम्पूर्ण सदन और सभी माननीय सदस्यों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा है ।